राष्ट्रीय संस्करण

भारतीय ग्रैंडमास्टर हंपी बनीं महिलाओं की विश्व रैपिड चैंपियन >>14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 202

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 30 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सात करोड़ से ज्यादा पाठकों के साथ दैनिक जागरण फिर शीर्ष पर

जेएनएन, नई दिल्ली : पाठकों के भरोसे पर लगातार खरा उतरते हुए दैनिक जागरण ने फिर खुद को देश का शीर्ष समाचार पत्र साबित किया है। 'इंडियन रीडरशिप सर्वे' (आइआरएस) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, सात करोड़ से ज्यादा पाठकों के साथ दैनिक जागरण की लोकप्रियता और साख मजबूत बनी हुई है।

मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) ने 2019 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए आइआरएस के आंकड़े जारी किए हैं। एमआरयूसी के अनुसार, तीसरी तिमाही में शहरी पाठकों में अखबार की पहुंच 52 फीसद पर कायम है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 31 फीसद हो गया है। पाठकों के भरोसे के दम पर ही पिछले साल दैनिक जागरण को 'दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज ब्रांड' का खिताब भी मिला था। विश्वसनीयता, सटीक जानकारी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले अपने अभियानों की बदौलत दैनिक जागरण ने एक अलग पहचान बनाई है। सात करोड़ पाठकों के साथ ने इस पहचान को और मजबूती दी है।

युवाओं को नापसंद है अराजकता : मोदी

संबोधन ▶ साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने युवाओं को दी देश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी

युवा सिस्टम फॉलो करते हैं और जरूरत पड़ने पर सवाल भी उठाते हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

साल के आखिरी 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और दलों की राजनीति पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का युवा अराजकता, अव्यवस्था, परिवारवाद और जातिवाद पसंद नहीं करता है। वह सिस्टम को फॉलो करना पसंद करते है और अगर सिस्टम काम न करे तो बेखौफ होकर सवाल करता है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं की पीठ पर हाथ फेरते हुए यह बताया कि हाल के दिनों की हिंसा युवाओं का आक्रोश नहीं था बल्कि उनका दुरुपयोग किया गया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को याद भी दिलाया कि उसका परिवारवाद युवाओं को कभी नहीं भा सकता है। मोदी ने युवाओं को भी सचेत किया कि अपनी ताकत पहचान कर तय करें कि वह युवावस्था का उपयोग किस तरह करते हैं। उनकी सकारात्मक ताकत ही देश की ताकत तय करेगी।

मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)।(प्रेट्र)

स्वामी विवेकानंद से लें सीख

स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपेक्षा की कि आगामी दशक में अपने दायित्वों के बारे में चिंतन करें क्योंकि यह युवाओं का दशक साबित होने वाला है। उन्होंने खासतौर से 21वीं सदी में जन्मे युवाओं को संबोधित किया और कहा, 'ये युवा सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं, निश्चित ही देश को गति देने वालों में इनकी भूमिका अहम व सक्रिय होगी।' ध्यान रहे कि इस सदी में जन्मे युवा पहली बार 2019 में लोकसभा में वोट देने के लायक हुए थे और अब हर साल लाखों ऐसे युवा मुद्दों की समझ के साथ ही प्रतिनिधि चुनने के योग्य होंगे।

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में समृद्ध है भारत का इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का समृद्ध इतिहास रहा है। इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान हमारी सभ्यता जितना ही प्राचीन है। मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से सूर्य के अध्ययन के लिए प्रस्तावित आदित्य सेटेलाइट का भी जिक्र किया। उन्होंने इसरो की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। मोदी ने पूर्वोत्तर के रहने वाले रिपुन का नाम भी लिया, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने का रास्ता तलाशने की अपील की है। रिपुन फिलहाल दक्षिण भारत में रहते हैं।

संसद में हुआ रिकॉर्ड काम

पीएम ने नए साल की शुभकामना देते हुए संसद में देशवासियों का भरोसा बढ़ाने का भी प्रयास किया। जनता को बधाई देते हुए कहा, आपके चुने प्रतिनिधियों ने संसद में साठ साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोनों सदनों में सौ फीसद से ज्यादा काम हुए।

यूं तो युवा वर्ग हमेशा से प्रधानमंत्री और भाजपा की प्राथमिकता में रहा है, पर 'मन की बात' की शुरुआत युवाओं से करने का खास अर्थ था। दरअसल पिछले दिनों सीएए को लेकर जिस तरह राजनीतिक दलों ने विश्वविद्यालयों को आंदोलन में शामिल किया, उस पर पीएम ने उंगली उठाई। मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह प्रदर्शन के दौरान आगजनी और अराजकता फैली वह युवाओं का काम नहीं हो सकता है। भाजपा और पीएम की ओर से पहले भी कहा जाता रहा है कि प्रदर्शन राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। मोदी ने युवाओं के इस अधिकार को स्वीकारा कि अगर सिस्टम काम न करे तो वे आवाज उठाएं। कहा, 'कभी कहीं सिस्टम रिस्पांड न कर रहा हो तो वह सवाल उठाते हैं.. यह सोशल मीडिया जनरेशन है, कुछ गलत हो रहा हो तो तत्काल वीडियो बनाकर समाज को सतर्क कर देता है, वह खुद सिस्टम का पालन पसंद करता है और दूसरों से भी यही अपेक्षा करता है।'

स्वदेशी अपनाएं, स्वरोजगार बढ़ाएं : पीएम ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि 2022 में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने तक सभी स्थानीय उत्पाद खरीदने का प्रयास करें ताकि स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिले। मोदी ने स्वरोजगार की दिशा में प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश के कादीपुर की महिलाओं का भी उल्लेख किया, जिन्होंने चप्पल बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद संयंत्र स्थापित किया है। मोदी ने फूलपुर के पुलिसकर्मियों की भी सराहना की, जिन्होंने इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने व परिवार के लिए इनसे चप्पल खरीदना शुरू किया है। मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हिमायत योजना का जिक्र करते हुए कहा, इससे प्रदेश के 18 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और अब वह आगे बढ़ रहे हैं।

गरीबों की करें मदद : प्रधानमंत्री ने लोगों से गरीबों की मदद के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को छोटे-छोटे समूह बनाकर समाज की प्रगति में योगदान देना चाहिए। इस संदर्भ में मोदी ने बिहार के बेतिया जिले के संकल्प-95 का जिक्र भी किया। यह पश्चिमी चंपारण के केआर हाईस्कूल के 1995 बैच के छात्रों का समूह है। इन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में प्रयासरत हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज और कई अन्य संस्थान भी इनके साथ जुड़े हैं।

45 लाख पूर्व सैनिकों का निजी डाटा नहीं लौटाने पर रिपोर्ट दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के लिए 45 लाख पूर्व सैनिकों की व्यक्तिगत जानकारी वाले डाटाबेस को वापस नहीं करने पर रक्षा मंत्रालय ने निजी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला आरटीआइ आवेदनों व कोमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) के पत्राचार के जरिये उजागर हुआ है। बत्रा को हाल ही में रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईमेल किया था जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (एक्स सर्विसमैन कांटिब्यूट्री हेल्थ स्कीम-ईसीएचएस) में नामांकित 45 लाख पूर्व सैनिकों के निजी डाटा को नहीं सौंपने वाली निजी कंपनी के खिलाफ 19 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। बत्रा ने आरटीआइ आवेदन के जरिये मुद्दे से संबंधित 'फाइल नोटिंग्स' मांगी थीं।

ईसीएचएस भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अफसरों और उनके आश्रितों को मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। आरटीआइ आवेदन के जवाब में प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि फर्म की ओर से 'गोपनीयता प्रमाणपत्र' के रूप में किसी भी लिखित पुष्टि के अभाव में 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (ईसीएचएस) के लाभार्थियों के डाटाबेस की सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जा सकती है।'

2010 में रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ पांच साल का अनुबंध किया था पेज>>3

सरोकार

रोशन किया अमिताभ से लेकर अंबानी तक का आशियाना

कोलकाता : हुगली जिले का चंदननगर शहर जगद्धात्री पूजा व लाइटिंग के लिए विख्यात है। यहां की बत्तियों से बिग बी और मुकेश अंबानी का घर तक रोशन हो चुका है। इनके पीछे हाथ है लाइट आर्टिस्ट सुप्रीम कुमार पाल का। (पेज-11)

जागरण विशेष

बिहार में पांच बेजुबान, चला रहे हुनर की दुकान

पटना : पांच दोस्तों की जुबां तो नहीं है, मगर इनका हुनर बोलता है। सभी दोस्त चिराग टेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। इनकी दिव्यांगता कभी काबिलियत के आड़े नहीं आई। इस दुकान से ही इनका परिवार चल रहा है। (पेज-11)

बेअसर होगी कश्मीर पर ओआइसी की बैठक

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▶ पाक के कहने पर सऊदी अरब बुला सकता है विशेष बैठक

▶ बैठक बाद जारी होने वाले बयान को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं भारत

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भले ही कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) की विशेष बैठक बुलाने की सहमति बनी हो लेकिन इसकी वजह से भारत की सऊदी अरब या ओआइसी के अधिकांश दूसरे देशों से रिश्तों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत ओआइसी के सभी प्रमुख देशों के साथ लंबी रणनीतिक साझेदारी की नींव रख चुका है। साथ ही ओआइसी की विश्व पटल पर बेहद कमजोर होती साख भी एक वजह है कि भारत प्रतिक्रिया जताने के बजाए शांत है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से प्रस्तावित यह बैठक कब और कहां होगी, इसकी भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊदी पिछले शुक्रवार इस्लामाबाद पहुंचे जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी व पीएम इमरान खान से हुई। भेंट के बाद पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि, 'कुरैशी ने भारत के कश्मीर, सीएए व एनआरसी का मुद्दा उठाया। बातचीत में कश्मीर को लेकर ओआइसी की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई है।' इस बयान के बाद ही भारत व पाक के मीडिया में यह खबरें आईं की कश्मीर पर विशेष बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि पाक के कहने पर सऊदी अरब ने ओआइसी की विशेष बैठक बुलाने की बात मान ली है। दरअसल, सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने मलेशिया व तुर्की की अगुवाई में इस्लामिक देशों की एक दूसरी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इसके एवज में ही पाक सरकार ने कश्मीर पर ओआइसी की विशेष बैठक बुलाने की मांग रखी थी।

वैसे कश्मीर पर ओआइसी पहले भी तल्ख टिप्पणी करता रहा है, इसके बावजूद अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। कई देश भारत को आश्वस्त करते रहे हैं कि ओआइसी का बयान उनके द्विपक्षीय रिश्तों से अलग है। पिछले वर्ष पाक के गंभीर एतराज के बावजूद ओआइसी बैठक में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसमें हिस्सा लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया है। इन दोनों देशों ने अभी तक कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। 30 अक्टूबर, 2019 को जब मोदी रियाद की यात्रा पर थे तब दोनों देशों के बीच तीन सुरक्षा समझौते हुए जिसमें एक रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन को लेकर था। इस तरह का परिषद सऊदी अरब ने विश्व के आठ देशों के साथ करने का फैसला किया है और इसमें पाकिस्तान नहीं है। दुनिया में जब साफ व स्वच्छ ईंधन की मांग बढ़ रही है तो भारत ओआइसी के सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, नाइजीरिया जैसे देशों का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार देश है। इन देशों में 70 लाख भारतीय काम करते हैं और कोई भी दूसरा मुल्क इतने बड़े प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध नहीं करा सकता।

ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय सऊदी अरब के साथ रिश्तों को लेकर आश्वस्त है। देश के प्रमुख रणनीतिक व कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी कहते हैं, 'यह सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को नियंत्रण में रखने का एक संकेत है। बैठक को होने में महीनों लग जाएंगे। वैसे भी ओआइसी पहले भी कई बार कश्मीर पर बहस कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी कोई खास अहमियत नहीं है।'

झारखंड के 11वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने ली शपथ, सरकार ने किया पहला फैसला

खत्म होंगे पत्थलगड़ी समर्थकों पर देशद्रोह के केस

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ शपथग्रहण के दौरान बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे

झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले फैसले में हेमंत सोरेन ने पत्थलगड़ी समर्थकों पर से देशद्रोह के मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उनका यह फैसला चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में शुरुआत माना जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 6 से 8 जनवरी 2020 तक विधानसभा का पहला सत्र लाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने तीन फैसले और अन्यान्य के तहत सात मामलों पर विचार कर सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले हेमंत ने रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम के अलावा राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथग्रहण के दौरान बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

हेमंत सोरेन जागरण

यह था पत्थलगड़ी आंदोलन : आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें गांव के श्मशान से लेकर गांव की सीमा तक पत्थर गाड़कर संदेश दिया जाता है। गांव और जमीन की सीमा इंगित करने, किसी व्यक्ति की स्मृति में, महत्वपूर्ण अवसरों को याद रखने तथा समाज के महत्वपूर्ण फैसले को लोगों तक पहुंचाने के लिए धरती में पत्थर गाड़ते हैं। इसका पारंपरिक महत्व किसी सरकारी दस्तावेज या सीमांकन से ज्यादा है। इसे ही पत्थलगड़ी कहा जाता है। यही पत्थलगड़ी क्षेत्रों में सरकार को नकारने तथा स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के आंदोलन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पत्थलगड़ी अभियान के तहत आदिवासी अपने संदेश को पत्थर पर लिखकर गांव की सीमा के पास गाड़ देते हैं। इस पर लिखा होता है कि गैर आदिवासी को बिना अनुमति गांव में प्रवेश नहीं करना है।

हेमंत के बहाने एकजुट हुए भाजपा विरोधी दल

राज्य ब्यूरो, रांची : हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपा विरोधी दलों के मेगा शो के तौर पर देखा जा रहा है। एक मंच पर इससे पहले इतने ज्यादा नेताओं का जुटान बंगलुरु में हुआ था, जब जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। इस समारोह में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के कद्दावर नेता एमके स्टालिन, कनिमोझी, टीआर बालू और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर वामदलों की अग्रिम कतार के सीताराम येचुरी, डी राजा ने मौजूदगी दर्ज कराई। (पेज 4 पर)

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का निधन

उडुपी : दक्षिण भारत के प्रमुख धर्मगुरुओं में एक पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 88 वर्षीय स्वामीजी रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कर्नाटक सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। द्वैतवाद के दार्शनिक मध्वाचार्य द्वारा स्थापित अष्ठ मठों के विश्वेश तीर्थ सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे। 19 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (पेज-7)

स्वामी विश्वेश तीर्थ का फाइल फोटो। प्रेट्र

शीर्ष 50 कंपनियों ने 59,600 करोड़ कर्ज चुकाया

▶ बैलेंसशीट सुधारने को चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनियों ने घटाया कर्ज

▶ बैंकों से नया कर्ज मिलने में दिक्कत देख अपनाया पिछला भुगतान करने का रास्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की शीर्ष 50 कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान 59,600 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है। कंपनियों ने अपनी बैलेंसशीट को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। इससे कंपनियों को बैंक से मिलने वाले कर्ज में सुधार होगा। पिछले कुछ समय के दौरान इन कंपनियों को घरेलू बैंकों से मिलने वाले कर्ज में गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में कंपनियों ने 43,000 करोड़ रुपये का कर्ज घटाया था।

इस समय कंपनियां फंड जुटाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। इसके अलावा आइबीसी जैसे कानून के चलते भी कंपनियां अपना कर्ज कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस दौरान इन कंपनियों द्वारा विदेश से जुटाए जाने वाले फंड में बड़ा इजाफा हुआ है। इसी वर्ष अक्टूबर में यह 341 करोड़ डॉलर (करीब 24 हजार करोड़ रुपये) रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले दो गुना है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को जारी फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि आम ग्राहकों की तरफ से कर्ज की मांग बढ़ी है। लेकिन कंपनियों द्वारा कर्ज घटाने के चलते कॉरपोरेट ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज पर दबाव पड़ा है।

प्रतीकात्मक फोटो

आरबीआइ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक बैंकों द्वारा दिए कर्ज में महज 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों के कर्ज देने की विकास दर 13.3 प्रतिशत रही थी, जिसके चालू वित्त वर्ष में घटकर 6.5 से सात प्रतिशत तक रह जाने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा दिए कर्ज में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2018-19 में यह बढ़ोतरी 5.4 लाख करोड़ रुपये की रही थी। लेकिन चालू वित्त वर्ष में छह दिसंबर तक यह बढ़ोतरी महज 80,000 करोड़ रुपये की रही है।

उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पाले ने बढ़ाई दिक्कतें

नई दिल्ली : शीतलहर के बाद पाला पड़ने से उत्तर भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के कारण 22 वर्षों के सबसे लंबे ठंड के दौर से गुजरे दिल्ली वालों को रविवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। कोहरे के कारण रेल और वायु यातायात प्रभावित है। कश्मीर के विक्षोभ व उत्तर-पश्चिम हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी, कोहरे व शीतलहर का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह औसत न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा उत्तर-पश्चिम से हवा की दिशा में तेजी से बदलाव शुरू होने से हुआ। (पेज-6)

कठघरे में कांग्रेस

तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने कहा था, एनपीआर से नहीं एनआरसी से तय होगी नागरिकता, एनपीआर और एनआरसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सवालों के घेरे में

मनमोहन सरकार ने भी कही थी एनआरसी लाने की बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 2011-12 में संसद में बताया था, एनपीआर के बाद आएगा एनआरसी

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़कर धरना प्रदर्शन और आंदोलन में जुटी कांग्रेस कठघरे में आ गई है। दरअसल सत्ता में रहते हुए वह खुद भी एनआरसी लाने की बात करती रही है। मनमोहन सरकार दो ने साफ कहा था कि वह एनआरसी लाने का इरादा रखती है और नागरिकता उसी के आधार पर तय होगी। संसद में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एनपीआर में सभी दस उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों के निशान, फोटो आदि लिए जाएंगे और फिर कार्ड दिए जाएंगे लेकिन वह नागरिकता का सुबूत नहीं होगा। नागरिकता अधिकार उसी को मिलेगा जिसका नाम एनआरसी में होगा। यह एनपीआर के सबसेट के रूप में बाद में आएगा।

कांग्रेस ने शनिवार को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर संविधान की दुहाई देते हुए सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध किया था। विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि एनआरसी से मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में होगी। विपक्षी दलों की सरकार वाले कुछ राज्यों ने एनपीआर लागू से भी मना कर दिया है। लेकिन सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का विचार अलग था। अगस्त 2011 में गुजरात के भाजपा सांसद सीआर पाटिल व अन्य तथा अगस्त 2012 में हरिन पाठक और योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में गृहमंत्रालय से लिखित सवाल के जरिए एनपीआर पर जवाब मांगा था। मजे की बात यह है कि दोनों ही सवालों में कहीं भी एनआरसी का जिक्र नहीं था। यह पूछा गया था कि सरकार कैसे तय करेगी कि एनपीआर के बाद जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र का गलत तरीके से नागरिकता के सुबूत के रूप में दुरुपयोग नहीं होगा।

मनमोहन सिंह फाइल फोटो

मनमोहन सरकार की तरफ से दिए गए दोनों सवालों के जवाब लगभग एक समान थे। इनमें बताया गया था कि पांच साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों की उंगलियों और दोनों आंखों की पुतलियों के निशान लिए जाएंगे। एनपीआर डाटा से आधार को जोड़ा जाएगा और ऐसे नामों के साथ तैयार लिस्ट को समाज, समुदाय, ग्राम सभा, वार्ड समिति के बीच जारी किया जाएगा ताकि कोई चाहे तो किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। संवेदनशील इलाकों में पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी। यह भी साफ किया गया था कि एनपीआर कार्ड मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि हर कोई भारतीय नागरिक है। जितेंद्र सिंह ने साफ कहा था, 'निवास पहचान पत्र (रेजिटेंड आइडेंटिटी कार्ड) से नागरिकता नहीं मिलेगी। हर कार्ड पर साफ लिखा होगा कि यह कार्ड किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं देता है। हर किसी की नागरिकता अलग से तय होगी जब एनआरसी की प्रक्रिया होगी। यह एनपीआर का ही अगला हिस्सा होगा।'

जाहिर है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी को मुस्लिम विरोधी और भाजपा का एजेंडा बताने वाली कांग्रेस को यह भी साफ करना होगा कि विपक्ष में रहते हुए उसके विचार क्यों बदल गए। ध्यान रहे कि शुरुआत के कुछ दिनों में कांग्रेस चुप थी लेकिन जब वाम और तृणमूल कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर लीड लिया तो कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। यह भी ध्यान रहे कि जब असम में एनआरसी लागू हुआ तो शुरुआती हिचक के बाद कांग्रेस ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसका समर्थन ही किया था।

कानून पर सियासत (विशेष) पेज>>5

डीडीसीए की वार्षिक आमसभा में झड़प के बाद जमकर हाथापाई

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

▶ मंच पर ही भिड़े सचिव तिहारा के समर्थक और कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश

▶ डीडीसीए ने न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की वार्षिक आमसभा (एजीएम) रविवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में झड़प और हाथापाई के बीच हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगाई गई। एजीएम में झड़प होने की आशंका के चलते बैठक को कैमरे की निगरानी में कराया गया, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। हालांकि, बैठक में डीडीसीए ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया। वर्मा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बदर दुरेज अहमद की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति बदर ने एक दिन पहले ही डीडीसीए सदस्यों को संयम बरतने के लिए कहा था।

थप्पड़ और घूंसे चले : एजीएम में जब मंच से डीडीसीए सचिव विनोद तिहारा प्रस्ताव पास कराने के लिए घोषणा कर रहे थे, तभी भाजपा विधायक और कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने विरोध दर्ज कराया। बात इतनी बढ़ गई कि मंच पर ही हाथापाई होने लगी। संयुक्त सचिव राजन मनचंदा उठकर आए तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया। इस दौरान तिहारा, ओमप्रकाश को समझाते दिखे। मनचंदा गुट का आरोप है कि विरोधी गुट के मकसूद आलम ने बदतमीजी की। वहीं, तिहारा गुट का कहना है कि माहौल को विपक्ष ने जानबूझकर खराब किया। डीडीसीए के निदेशक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। बैठक के दौरान सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर को छीन लिया गया।

एजीएम में सभी प्रस्ताव पारित पेज>>14